



“निगम से संबंधित शासन प्रणाली का अध्ययन”

डॉ. राजू रेदास

शोधार्थी - डी-लिट (वाणिज्य), अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,
रीवा (म०प्र०) भारत.

परिचय - Introduction :-

ए बोर्ड कल्चर आफ कार्पोरेट गवर्नेन्स में व्यापार लेखक गेबेरियल ओडोनोवैन कार्पोरेट प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वह ‘एक आंतरिक व्यवस्था है, जिसमें शामिल हैं नीतियां, प्रक्रियाएं और लोग, जो अच्छे व्यापार ज्ञान, वस्तुगत दृष्टि, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा के साथ प्रबंधन गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करते हुए, शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठेस कार्पोरेट प्रशासन, बाहरी बाजार प्रतिबद्धता और कानून, और साथ ही, नीतियों और प्रक्रियाओं को सुरक्षित रखने वाली एक स्वस्थ बोर्ड संस्कृति पर निर्भर है।



ओडोनोवैन का आगे कहना है कि ‘एक कंपनी के कार्पोरेट प्रशासन की अनुभूत गुणवत्ता, उसके शेयर की कीमत और पूंजी जुटाने की लागत को प्रभावित कर सकती है। गुणवत्ता का निर्धारण होता है वित्तीय बाजारों, कानून और अन्य विदेशी बाजार की शक्तियों से और इस आधार पर कि नीतियों और प्रक्रियाओं को कैसे लागू किया गया है तथा लोगों का नेतृत्व किस प्रकार हो रहा है। बाह्य शक्तियां, अधिकांशतः किसी भी बोर्ड के नियंत्रण से बाहर के घेरे में रहती हैं। आंतरिक परिवेश बिल्कुल अलग बात है और कंपनियां अपनी बोर्ड संस्कृति के जरिए प्रतियोगियों से अंतर पहचानने का मौका देती हैं। अब तक, ज्यादातर कार्पोरेट प्रशासन बहस विधायी नीति, धोखाधड़ी की गतिविधियों का निवारण और पारदर्शिता नीति पर केंद्रित रही हैं, जो कार्यपालकों को, कारण की बजाय लक्षणों के उपचार के लिए बहकाती है, यह दीर्घकालिक सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से संरचना, संचालन और कंपनी के नियंत्रण की प्रणाली है, ताकि शेयरधारकों, लेनदारों, कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं की संतुष्टि और कानूनी तथा नियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के अतिरिक्त पर्यावरण तथा स्थानीय सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव हो सके।

कार्पोरेट प्रशासन पर SEBI समिति (भारत) की रिपोर्ट, निगम के वास्तविक मालिकों के रूप में शेयरधारकों के असंक्राम्य अधिकारों के प्रबंधन द्वारा स्वीकृति और शेयरधारकों की ओर से न्यासी के रूप में अपनी भूमिका के तौर पर, कार्पोरेट प्रशासन को परिभाषित करती है। यह मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, नैतिक व्यापार आचरण और कंपनी के प्रबंधन में निजी तथा कार्पोरेट निधियों के बीच अंतर करने से संबंधित है।¹ यह परिभाषा न्यासिता संबंधी गांधीवादी सिद्धांत और भारतीय संविधान के निदेशक सिद्धांतों से ली गई है। कार्पोरेट प्रशासन को आचार और नैतिक कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। प्रोफेसर ब्रजलाल सापोवादिया के अनुसार कार्पोरेट प्रशासन व्यक्तिगत हित का सन्स्था के लिये भोग देना एवम सन्स्था का हित समाज के लिए बलिदान करना है

कार्पोरेट प्रशासन के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है। कार्पोरेट प्रशासन उस तरीके को परिभाषित करता है जिस तरह से एक कार्पोरेट उद्यम को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यह कार्पोरेट मूल्यों, मानदंडों और नैतिकता का वर्णन करता है। यह एक कार्पोरेट उद्यम के विकास की दिशा की व्याख्या करता है।

“कार्पोरेट प्रशासन कार्पोरेट प्रबंधकों, निदेशकों और इक्विटी के प्रदाताओं, लोगों और संस्थानों के बीच का संबंध है जो रिटर्न कमाने के लिए अपनी पूंजी को बचाते और निवेश करते हैं।

पृष्ठभूमि :-

कारपोरेट गवर्नेंस की आवश्यकता निगमों में हितधारकों के बीच हितों के टकराव को कम करने की आवश्यकता का अनुसरण करती है। हितों के ये टकराव शेयरधारकों और ऊपरी प्रबंधन (प्रमुख-एजेंट समस्याओं) और शेयरधारकों (प्रमुख-प्रमुख समस्याओं) दोनों के बीच विचलन के परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं, हालांकि अन्य हितधारक संबंध भी कारपोरेट के माध्यम से प्रभावित और समन्वित होते हैं।

शासन कारपोरेट गवर्नेंस को और अधिक संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया है “कानून और ध्वनि दृष्टिकोण की एक प्रणाली जिसके द्वारा निगमों को निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है, जो प्रबंधन और निदेशकों के कार्यों की निगरानी के इरादे से आंतरिक और बाहरी कारपोरेट संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इस तरह, एजेंसी के जोखिमों को कम करते हैं।

कारपोरेट प्रशासन को “एक निगम के बाहरी निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन के कार्य” के रूप में भी परिभाषित किया गया है और शासन की परिभाषा से संबंधित है “एक इकाई, प्रक्रिया या संसाधन को बाहरी रूप से निर्देशन, नियंत्रण और मूल्यांकन करने का कार्य”। इस अर्थ में, शासन और कारपोरेट प्रशासन प्रबंधन से अलग हैं क्योंकि शासन को शासित होने वाली वस्तु के लिए बाहरी होना चाहिए। गवर्निंग एजेंटों का व्यक्तिगत नियंत्रण नहीं होता है, और वे उस वस्तु का हिस्सा नहीं होते हैं जिस पर वे शासन करते हैं। उदाहरण के लिए, सीआईओ के लिए आईटी कार्य को नियंत्रित करना संभव नहीं है। वे कार्य की रणनीति और प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह हैं। जैसे, वे आईटी फंक्शन को “प्रबंधित” करते हैं वे इसे “शासन” नहीं करते हैं। उसी समय, बोर्ड द्वारा अधिकृत कई नीतियां हो सकती हैं, जिनका सीआईओ अनुसरण करता है। जब सीआईओ इन नीतियों का पालन कर रहा है, तो वे “शासन” गतिविधियां कर रहे हैं क्योंकि नीति का प्राथमिक उद्देश्य शासन के उद्देश्य की पूर्ति करना है। बोर्ड अंततः आईटी फंक्शन को “शासन” कर रहा है क्योंकि वे फंक्शन के बाहर खड़े हैं और केवल स्थापित नीतियों, प्रक्रियाओं और संकेतकों के आधार पर आईटी फंक्शन को बाहरी रूप से निर्देशित, नियंत्रित और मूल्यांकन करने में सक्षम हैं। इन नीतियों, प्रक्रियाओं और संकेतकों के बिना, बोर्ड के पास शासन करने का कोई तरीका नहीं है, आईटी कार्य को किसी भी तरह से प्रभावित करना तो दूर की बात है।

कारपोरेट प्रशासन के पक्षकार :-

कारपोरेट प्रशासन में शामिल पक्षों में नियामक निकाय (मुख्य कार्यपालक अधिकारी, निदेशक मंडल, प्रबंधन, शेयरधारक और लेखा-परीक्षक) सम्मिलित है। भाग लेने वाले अन्य हितधारकों में शामिल हैं आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी, लेनदार, उपभोक्ता और सामान्य तौर पर समुदाय निगमों में, शेयरधारक प्रबंधक को मूलधन के सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए निर्णय का अधिकार सौंपता है। नियंत्रण से स्वामित्व का यह अलगाव का अर्थ है, शेयरधारकों द्वारा प्रबंधकीय फैसलों पर प्रभावी नियंत्रण में कमी। दोनों पक्षों के बीच इस अलगाव के परिणामस्वरूप आंशिक रूप से, कारपोरेट प्रशासन नियंत्रण की एक प्रणाली कार्यान्वित होती है, ताकि शेयरधारकों और प्रबंधकों के प्रोत्साहन राशि के सुयोजन में मदद मिले। निवेशकों के इच्छित पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, स्वामित्व और नियंत्रण की समस्याओं के अलगाव को उलटने का एक मौका है, क्योंकि स्वामित्व उतना फैला हुआ नहीं है।

कारपोरेट प्रशासन में अक्सर निदेशक मंडल प्रमुख भूमिका निभाता है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि संगठन की रणनीति का समर्थन, दिशात्मक नीति का विकास, नियुक्ति, पर्यवेक्षण करें और वरिष्ठ कार्यपालकों को पारिश्रमिक दें तथा उसके मालिकों और प्राधिकारियों को संगठन की जवाबदेही सुनिश्चित करें।

कंपनी सचिव, जो अमेरिका में कारपोरेट सचिव के रूप में जाना जाता है और अक्सर एक चार्टर्ड सचिव के रूप में निर्दिष्ट होता है, यदि चार्टर्ड सचिव और प्रशासक संस्थान (ICSA) द्वारा योग्य पाया जाए, एक उच्च श्रेणी वाला पेशेवर, जो कारपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने, प्रभावी संचालन, अनुपालन और प्रशासन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

कारपोरेट प्रशासन के सभी पक्षकारों की, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, संगठन के प्रभावी निष्पादन में दिलचस्पी होती है। निदेशक, कर्मचारी और प्रबंधन को वेतन, लाभ और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, जबकि शेयरधारकों को पूंजी पर प्रतिफल मिलता है। ग्राहकों को माल और सेवाएं हासिल होती हैं या आपूर्तिकर्ताओं को उनके उत्पादों या सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त होती है। बदले में ये व्यक्ति पूंजी के प्राकृतिक, मानवीय, सामाजिक या अन्य रूपों में मूल्य प्रदान करते हैं।

एक प्रमुख कारक, व्यक्ति का संगठन में भाग लेने का निर्णय, जैसे वित्तीय पूंजी प्रदान कर और विश्वास कि उन्हें संगठन के लाभ का एक उचित हिस्सा मिलेगा। अगर कुछ पक्षों को उनके उचित प्रतिफल से ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिभागी भाग न लेने का चयन कर सकते हैं, जिससे संगठनात्मक पतन होगा।

कोड और दिशानिर्देश :-

कारपोरेट गवर्नेंस सिद्धांत और कोड विभिन्न देशों में विकसित किए गए हैं और स्टॉक एक्सचेंजों, निगमों, संस्थागत निवेशकों, या सरकारों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समर्थन से निदेशकों और प्रबंधकों के संघों (संस्थानों) से जारी किए गए हैं। एक नियम के रूप में, इन शासन सिफारिशों का अनुपालन

कानून द्वारा अनिवार्य नहीं है, हालांकि स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग आवश्यकताओं से जुड़े कोड का एक जबरदस्त प्रभाव हो सकता है।

निगम के सिद्धांत :-

अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों के मुख्य तत्वों में शामिल हैं, ईमानदारी, विश्वास और अखंडता, खुलापन, निष्पादन अभिविन्यास, जिम्मेदारी और जवाबदेही, परस्पर सम्मान और संगठन के प्रति वचनबद्धता महत्वपूर्ण है कि निदेशक और प्रबंधन कैसे प्रशासन का एक मंडल विकसित करते हैं जो कॉर्पोरेट प्रतिभागियों के मूल्यों का सुयोजन करता है और फिर इस माडल का उसके प्रभाव को आंकने के लिए आधिक मूल्यांकन करना. विशेष रूप से, वरिष्ठ कार्यपालक का आचरण सत्यनिष्ठ और नैतिक हो, खास तौर पर वास्तविक और स्पष्ट परस्पर विरोधी हितों के मामले में, तथा वित्तीय विवरणियों में प्रकटन सामान्यतः स्वीकृत कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों में शामिल हैं :-

- **शेयरधारकों के अधिकार और न्यायोचित व्यवहार :-** संगठन द्वारा शेयरधारकों के अधिकारों का सम्मान और शेयरधारकों को उनके अधिकारों के प्रयोग में सहायता. वे शेयरधारकों को बोधगम्य और सुलभ तरीके से, प्रभावी तौर पर जानकारी उपलब्ध कराते हुए और सामान्य बैठकों में शेयरधारकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करने में मदद दे सकते हैं।
- अन्य हितधारकों के हित: संगठन को जानना चाहिए कि अन्य सभी हितधारकों के प्रति उनके कानूनी और अन्य दायित्व हैं।
- **मंडल की भूमिका और जिम्मेदारियां :-** मंडल को व्यवस्थित कौशल और समझदारी की जरूरत है, ताकि विभिन्न व्यावसायिक मुद्दों से निपटने और प्रबंधन के निष्पादन की समीक्षा और उसे चुनौती में सक्षम हों यह पर्याप्त आकार में और अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, उचित स्तर की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कार्यपालक और गैर कार्यपालक निदेशकों के समुचित मिश्रण के बारे में मुद्दे मौजूद हैं।
- **ईमानदारी और नैतिक व्यवहार :-** नैतिक और उत्तरदायी निर्णय करना न केवल सार्वजनिक संबंध के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जोखिम प्रबंधन और कानूनी मुकदमों को टालने के लिए भी एक आवश्यक तत्व है। संगठनों द्वारा अपने निदेशक और कार्यपालकों के लिए आचार संहिता विकसित करनी चाहिए, जो नैतिक और उत्तरदायी निर्णय लेने को बढ़ावा दे हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि कंपनी द्वारा व्यक्तियों की सत्यनिष्ठा और नैतिकता पर निर्भरता, अंततः विफलता के लिए बाध्य होगी. इस कारण, फर्म द्वारा नैतिक और कानूनी सीमाओं के बाहर जाने पर होने वाली जोखिम को कम करने के लिए, कई संगठन, अनुपालन और नैतिक कार्यक्रम स्थापित करते हैं।
- **प्रकटीकरण और पारदर्शिता :-** संगठन द्वारा मंडल और प्रबंधन की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट और सार्वजनिक तौर पर समझाना चाहिए ताकि शेयरधारकों को एक हद तक जवाबदेही उपलब्ध करा सकें. उन्हें कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदनों की सत्यनिष्ठा के स्वतंत्र सत्यापन और सुरक्षा के लिए प्रक्रियाओं को लागू करना चाहिए. संगठन से संबंधित वस्तुपरक मामलों का प्रकटीकरण समय पर और संतुलित होना चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके कि सभी निवेशकों को स्पष्ट, तथ्यात्मक जानकारी सुलभ है।

कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी सिद्धांतों से जुड़े मुद्दों में शामिल हैं :-

- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा-परीक्षक।
- इकाई के बाह्य लेखा-परीक्षकों की आजादी और उनके लेखा-परीक्षणों की गुणवत्ता
- निरीक्षण और जोखिम प्रबंधन
- एकक की वित्तीय विवरणियों की तैयारी का निरीक्षण
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए क्षतिपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा
- निदेशकों को उनके कर्तव्य-निर्वाह के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधन
- मंडल में पदों के लिए व्यक्तियों के नामांकन का तरीका
- लाभांश नीति

तंत्र और नियंत्रण :-

कॉर्पोरेट प्रशासन तंत्र और नियंत्रण, नैतिक जोखिम और प्रतिकूल चयन से उभरने वाली अक्षमताओं को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, प्रबंधकों के व्यवहार की देख-रेख के लिए, निवेशकों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सटीकता की पुष्टि एक स्वतंत्र अन्य पक्ष (बाह्य लेखा परीक्षक) द्वारा की जाती है। एक आदर्श नियंत्रण प्रणाली द्वारा प्रेरणा और क्षमता, दोनों का नियंत्रण होना चाहिए।

आंतरिक कार्पोरेट प्रशासन नियंत्रण :-

आंतरिक कार्पोरेट प्रशासन परिवीक्षक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है और फिर संगठनात्मक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करता है।

• **निदेशक मंडल द्वारा निगरानी :-** निदेशक मंडल, उसको हासिल शीर्ष प्रबंधन को नियुक्त, बरखास्त और भरपाई करने के कानूनी प्राधिकार के साथ, पूंजी निवेश पर निगरानी रखता है। नियमित रूप से मंडल की बैठकें, संभावित समस्याओं की पहचान, उन पर चर्चा, उनके परिहार को अनुमत करती है। जहां गैर कार्यपालक निदेशकों को अधिक स्वतंत्र माना जाता है, वे हमेशा अधिक प्रभावी कार्पोरेट प्रशासन में परिणत नहीं होते और निष्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते, अलग-अलग फर्मों के लिए अलग मंडल संरचना इष्टतम हैं। इसके अलावा, फर्म के कार्यपालकों पर निगरानी के प्रति मंडल की क्षमता, जानकारी तक उसकी पहुंच से जुड़ा कार्य है। कार्यपालक निदेशक निर्णय प्रक्रिया की बेहतर जानकारी रखते हैं और इसलिए शीर्ष प्रबंधन का मूल्यांकन उनके निर्णयों की गुणवत्ता के आधार पर करते हैं, जो वित्तीय निष्पादन के परिणामों में प्रतिफलित होता है, प्रत्याशित इसलिए यह तर्क दिया जा सकता है कि कार्यपालक निदेशक वित्तीय मानदंडों के परे देखते हैं।

• **आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और आंतरिक लेखा-परीक्षक :-** आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं, एकक के निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति, प्रबंधन और अन्य कर्मियों द्वारा कार्यान्वित नीतियां हैं, जो वित्तीय रिपोर्टिंग, परिचालन क्षमता और कानून तथा विनियमों के अनुपालन संबंधी उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करते हैं। आंतरिक लेखा-परीक्षक संगठन के कर्मचारी हैं, जो इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के डिजाइन और कार्यान्वयन और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को परखते हैं।

• **सत्ता संतुलन :-** सत्ता का आसान संतुलन बहुत आम है जल्द ही कि कोषाध्यक्ष से भिन्न व्यक्ति अध्यक्ष हो सत्ता के अलगाव के इस विनियोग को कंपनियों में आगे और विकसित किया जाता है, जहां अलग विभाग एक दूसरे के कार्यों की जांच करते हैं। एक समूह कंपनी-व्यापक प्रशासनिक बदलाव प्रस्तावित कर सकता है, दूसरा समूह समीक्षा करता है और परिवर्तनों को मना कर सकता है और तीसरा समूह जांच करता है कि तीनों समूहों के बाहर, लोगों के हितों (ग्राहक, शेयरधारक, कर्मचारी) का ध्यान रखा जा रहा है।

• **पारिश्रमिक :-** निष्पादन-आधारित पारिश्रमिक, व्यक्तिगत निष्पादन को वेतन के कुछ अनुपात से जोड़ते हुए डिजाइन किया गया है। यह नकद या गैर-नकद भुगतान जैसे शेयर और शेयर विकल्प, अधिवर्षिता या अन्य लाभों के रूप में हो सकता है। तथापि, ऐसी प्रोत्साहन योजनाएं, प्रतिक्रियात्मक हैं, यानि वे गलतियों या अवसरवादी व्यवहार के निवारण के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं कराती है और निकटदर्शी व्यवहार को प्रकाश में लाती है।

बाह्य कार्पोरेट प्रशासन नियंत्रण :-

बाह्य कार्पोरेट प्रशासन नियंत्रणों में हितधारकों द्वारा संगठन पर लागू बाहरी नियंत्रण सम्मिलित हैं :-

- प्रतियोगिता
- ऋण प्रसंविदाएं
- निष्पादन जानकारी की मांग और मूल्यांकन (विशेष रूप से वित्तीय विवरणियां)
- सरकारी विनियमन
- प्रबंधकीय श्रम बाजार
- मीडिया दबाव
- अधिग्रहण

आर्थिक सहयोग और विकास सिद्धांतों के लिए संगठन :-

कार्पोरेट गवर्नेंस पर सबसे प्रभावशाली दिशा-निर्देशों में से एक कार्पोरेट गवर्नेंस के जी20 / ओईसीडी सिद्धांत हैं, जिन्हें पहली बार 1999 में ओईसीडी सिद्धांतों के रूप में प्रकाशित किया गया था, 2004 में संशोधित किया गया था और 2015 में जी20 द्वारा फिर से संशोधित किया गया था। सिद्धांतों को अक्सर संदर्भित किया जाता है स्थानीय कोड या दिशानिर्देश विकसित करने वाले देशों द्वारा। ओईसीडी, अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्र के संघों और 20 से अधिक राष्ट्रीय कार्पोरेट गवर्नेंस कोड के काम पर निर्माण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय मानकों पर लेखा और रिपोर्टिंग (आईएसएआर) के विशेषज्ञों के अंतर सरकारी कार्य समूह का गठन किया गया ताकि वे अच्छी प्रथाओं पर अपना मार्गदर्शन तैयार कर सकें। कार्पोरेट प्रशासन प्रकटीकरण। इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत बेंचमार्क में पांच व्यापक श्रेणियों में पचास से अधिक विशिष्ट प्रकटीकरण आइटम शामिल हैं :-

- लेखा परीक्षा
- बोर्ड और प्रबंधन संरचना और प्रक्रिया
- संगठन में कार्पोरेट जिम्मेदारी और अनुपालन

- वित्तीय पारदर्शिता और सूचना प्रकटीकरण
- स्वामित्व संरचना और नियंत्रण अधिकारों का प्रयोग

निदेशक मंडल की जिम्मेदारियां :-

जनरल मोटर्स के बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जान जी-स्माले ने 1995 में लिखा: “निगम के सफल स्थायीकरण के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। उस जिम्मेदारी को प्रबंधन पर नहीं लगाया जा सकता है। एक निदेशक मंडल कंपनी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। बोर्ड की जिम्मेदारी है सीईओ चयन और उत्तराधिकार्य संगठन की रणनीति पर प्रबंधन को प्रतिक्रिया प्रदान करना वरिष्ठ अधिकारियों को मुआवजा देना वित्तीय स्वास्थ्य, प्रदर्शन और जोखिम की निगरानी और अपने निवेशकों और अधिकारियों के प्रति संगठन की जवाबदेही सुनिश्चित करना। बोर्डों में आमतौर पर अपना काम करने के लिए कई समितियाँ (जैसे, मुआवजा, नामांकन और लेखा परीक्षा) होती हैं।

कारपोरेट गवर्नेंस के ओईसीडी सिद्धांत (2004) बोर्ड की जिम्मेदारियों का वर्णन करते हैं इनमें से कुछ का सारांश नीचे दिया गया है : -

- बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया जाना चाहिए और कंपनी और उसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में उचित परिश्रम और देखभाल के साथ नैतिक रूप से और अच्छे विश्वास में कार्य करना चाहिए।
- कारपोरेट रणनीति, उद्देश्य निर्धारण, कार्यवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, पूंजी योजनाओं और वार्षिक बजट की समीक्षा और मार्गदर्शन करें।
- प्रमुख अधिग्रहण और विनिवेश की निगरानी करें।
- प्रमुख अधिकारियों का चयन करें, क्षतिपूर्ति करें, निगरानी करें और बदलें और उत्तराधिकार योजना की निगरानी करें।
- कंपनी और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हित के साथ प्रमुख कार्यकारी और बोर्ड के पारिश्रमिक (वेतन) को संरेखित करें।
- एक औपचारिक और पारदर्शी बोर्ड सदस्य नामांकन और चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
- अपने स्वतंत्र लेखा परीक्षा सहित निगम के लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग सिस्टम की अखंडता सुनिश्चित करें।
- सुनिश्चित करें कि आंतरिक नियंत्रण की उपयुक्त प्रणाली स्थापित की गई है।
- प्रकटीकरण और संचार की प्रक्रिया की देखरेख करें।
- जहां बोर्ड की समितियां स्थापित की जाती हैं, वहां उनके अधिदेश, संरचना और कार्य प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से परिभाषित और प्रकट किया जाना चाहिए।

वित्तीय रिपोर्टिंग और स्वतंत्र लेखा परीक्षक :-

निगम के आंतरिक और बाहरी वित्तीय रिपोर्टिंग कार्यों के लिए निदेशक मंडल की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी महत्वपूर्ण भाग ले रहे हैं, और बोर्डों आम तौर पर ईमानदारी और जानकारी लेखांकन की आपूर्ति के लिए उन पर निर्भरता के एक उच्च स्तर की है। वे आंतरिक लेखा प्रणालियों की देखरेख करते हैं, और निगम के लेखाकारों और आंतरिक लेखा परीक्षकों पर निर्भर हैं।

अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानकों और यूएस जीएपी के तहत वर्तमान लेखा नियम प्रबंधकों को विभिन्न वित्तीय रिपोर्टिंग तत्वों की पहचान के लिए माप के तरीकों और मानदंडों को निर्धारित करने में कुछ विकल्प की अनुमति देते हैं। स्पष्ट प्रदर्शन में सुधार के लिए इस विकल्प का संभावित अभ्यास उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना जोखिम को बढ़ाता है। गैर-प्रकटीकरण और मूल्यों के जानबूझकर मिथ्याकरण सहित वित्तीय रिपोर्टिंग धोखाधड़ी भी उपयोगकर्ताओं के सूचना जोखिम में योगदान करती है। इस जोखिम को कम करने और वित्तीय रिपोर्टों की कथित अखंडता को बढ़ाने के लिए, निगम की वित्तीय रिपोर्टों का एक स्वतंत्र बाहरी लेखा परीक्षक द्वारा लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए जो वित्तीय विवरणों के साथ एक रिपोर्ट जारी करता है।

चिंता का एक क्षेत्र यह है कि क्या आडिटिंग फर्म उस फर्म के लिए स्वतंत्र आडिटर और प्रबंधन सलाहकार दोनों के रूप में कार्य करती है जिसका वे आडिट कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप हितों का टकराव हो सकता है जो प्रबंधन को खुश करने के लिए क्लाइंट के दबाव के कारण वित्तीय रिपोर्टों की अखंडता को संदेह में रखता है। कर्पोरेट क्लाइंट की प्रबंधन परामर्श सेवाओं को शुरू करने और समाप्त करने की शक्ति, और अधिक मौलिक रूप से, लेखा फर्मों को चुनने और खारिज करने की शक्ति एक स्वतंत्र लेखा परीक्षक की अवधारणा के विपरीत है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिनियम के रूप में अधिनियमित परिवर्तन (कई कर्पोरेट घोटालों के बाद, एनरान घोटाले के साथ समापन) लेखा फर्मों को लेखा परीक्षा और प्रबंधन परामर्श सेवाएं दोनों प्रदान करने से रोकता है। भारत में मानक लिस्टिंग समझौते के खंड 4.9 के तहत इसी तरह के प्रावधान मौजूद हैं।

प्रणालीगत समस्याएं :-

- **सूचना की मांग :-** निदेशकों को प्रभावित करने के लिए, शेयरधारकों को एक मतदान समूह बनाने के लिए दूसरों के साथ गठबंधन करना चाहिए जो एक आम बैठक में प्रस्तावों को ले जाने या निदेशकों की नियुक्ति के लिए एक वास्तविक खतरा पैदा कर सकता है।
- **निगरानी लागत :-** अच्छी जानकारी का उपयोग करने वाले शेयरधारकों के लिए एक बाधा इसे संसाधित करने की लागत है, खासकर एक छोटे शेयरधारक के लिए। इस समस्या का पारंपरिक उत्तर कुशल-बाजार परिकल्पना है (वित्त में, कुशल बाजार परिकल्पना (EMH) का दावा है कि वित्तीय बाजार कुशल हैं), जो यह बताता है कि छोटे शेयरधारक बड़े पेशेवर निवेशकों के निर्णयों पर मुक्त सवारी करेंगे।
- **लेखांकन** जानकारी की आपूर्ति वित्तीय खाते निदेशकों की निगरानी के लिए वित्त प्रदाताओं को सक्षम करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में खामियां कंपोरेट प्रशासन की प्रभावशीलता में खामियों का कारण बनेंगी। इसे, आदर्श रूप से, बाहरी लेखा परीक्षा प्रक्रिया के कार्य द्वारा ठीक किया जाना चाहिए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बोर्ड की भूमिकाओं के अध्यक्ष का पृथक्करण :-

शेयरधारक निदेशक मंडल का चुनाव करते हैं, जो बदले में प्रबंधन का नेतृत्व करने के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को नियुक्त करते हैं। बोर्ड की प्राथमिक जिम्मेदारी सीईओ के चयन और प्रतिधारण से संबंधित है। हालांकि, कई अमेरिकी निगमों में सीईओ और बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका एक ही व्यक्ति के पास होती है। यह प्रबंधन और बोर्ड के बीच हितों का एक अंतर्निहित संघर्ष पैदा करता है।

संयुक्त भूमिकाओं के आलोचकों का तर्क है कि दो भूमिकाओं को अलग किया जाना चाहिए ताकि हितों के टकराव से बचा जा सके और खराब प्रदर्शन करने वाले सीईओ को आसानी से बदला जा सके। वारेन बफेट ने 2014 में लिखा था। “उन्नीस सार्वजनिक कंपनियों के बोर्ड में मेरी सेवा में, हालांकि, मैंने देखा है कि एक औसत सीईओ को बदलना कितना मुश्किल है यदि वह व्यक्ति भी अध्यक्ष है। (विलेख आमतौर पर हो जाता है, लेकिन लगभग हमेशा बहुत देर से। अधिवक्ताओं का तर्क है कि अनुभवजन्य अध्ययनों से यह संकेत नहीं मिलता है कि भूमिकाओं को अलग करने से शेयर बाजार के प्रदर्शन में सुधार होता है और यह शेयरधारकों पर निर्भर होना चाहिए कि फर्म के लिए कंपोरेट प्रशासन मंडल क्या उपयुक्त है। अमेरिकी कंपनियों की संयुक्त भूमिकाएँ थीं यह मई 2012 तक घटकर 57.2% हो गया। संयुक्त भूमिकाओं वाली कई अमेरिकी कंपनियों ने प्रबंधन से बोर्ड की स्वतंत्रता में सुधार के लिए “लीड डायरेक्टर” नियुक्त किया है। जर्मन और यूके की कंपनियों ने आम तौर पर लगभग 100% सूचीबद्ध कंपनियों में भूमिकाओं को विभाजित किया है। अनुभवजन्य साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि प्रदर्शन के मामले में एक मंडल दूसरे से बेहतर है। हालांकि, एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियां सीईओ/चेयर भूमिकाओं को संयुक्त करने की तुलना में अलग सीईओ को अधिक बार हटा देती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शैलर, ग्रेग- आस्ट्रेलिया में कंपोरेट प्रशासन का एक परिचय , पियर्सन एजुकेशन आस्ट्रेलिया, सिडनी, 2004,
2. कंपोरेट गवर्नेंस इंटरनेशनल जर्नल, “ए बोर्ड कल्चर ऑफ कंपोरेट गवर्नेंस, खंड 6 अंक 3 (2003)
3. “थियोरिस आफ कंपोरेट गवर्नेंस: द फिलसॉफिकल फाउंडेशन्स आफ कंपोरेट गवर्नेंस, “लंदन और न्यूयार्क रूटलेड्ज, ISBN 0-415-32308-8
4. जी20/ ओईसीडी कारपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांत “राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के कंपोरेट प्रशासन पर ओईसीडी दिशानिर्देश।
5. “कंपोरेट गवर्नेंस कंपोरेट सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबल बिजनेस के लिए फाउंडेशन
6. इंटरनेशनल कारपोरेट गवर्नेंस, प्रेंटिस हल, हार्लो, जनवरी, 2012
- 7- www.google-com/wikipedia-com
- 8- www-wikipedia-com